पत्रांक–14/डी0एल0ए0/(नीति) अभिलेख संधारण–14/2018–......36......../रा0,

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

कमलेश कुमार सिंहं, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः–12.01.2026

विषयः– राज्यान्तर्गत लोकहित में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण/अर्जन के समय भू–सत्यापन में वन विभाग को शामिल करने के संबंध में।

प्रसंगः– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 6499 दिनांक 17.11.2025 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक–13.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। प्रासंगिक पत्रों से राज्यान्तर्गत लोकहित में संचालित विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं यथा–एन0एच0 एवं रेलवे इत्यादि के लिए भूमि अधिग्रहण/अर्जन के समय अर्जनाधीन भूमि के संयुक्त भू–सत्यापन में वन विभाग को शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतएव प्रासंगिक पत्र में किये गये अनुरोध के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि राज्यान्तर्गत लोकहित में संचालित विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं यथा–एन0एच0 एवं रेलवे इत्यादि के लिए भूमि अधिग्रहण/अर्जन के समय अर्जनाधीन भूमि के संयुक्त भू–सत्यापन में वन विभाग को अचूक रूप से शामिल करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
7/1/26
(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–......36........../रा0,
दिनांकः–12.01.2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/1/26
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–......36........../रा0,
दिनांकः–12.01.2026

प्रतिलिपिः–आई.टी.मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर यथास्थान प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

7/1/26
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

(138)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:- यो011/PMG-05/2024 6499 /यो0वि0,पटना,दिनांक 27 नवम्बर,2025

प्रेषक,

कँवल तनुज
सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के समय संयुक्त भू-सत्यापन में वन विभाग को शामिल करने के संबंध में ।**

प्रसंगः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 13.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-**यथोक्त** ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सचिव

ज्ञापांक: यो011/PMG-05/2024 6499 /यो0वि0,पटना,दिनांक 27 नवम्बर,2025

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

अपर मुख्य सचिव कोषांग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पत्र डायरी सं० 11728
दिनांक 04/12/25

-FC-11/147/2024-FC

(129)

1/143142/2025

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: November, 2025

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),
All States Governments and Union territory Administrations

Sub: Involvement of local Forest Department in the joint field verification at the time of land acquisition to ascertain the involvement of forest lands in the projects – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above-mentioned subject and to state that several infrastructure and development projects, including those pertaining to Railways and National Highways, are facing delays on account of inadequate information provided by the State Governments regarding the status of land at the time of its identification or acquisition. It has often been observed that land jointly identified by officials of the Revenue Department of the State Government and the project proponent are subsequently found to be forest land.

To address such issues and ensure clear identification of forest land during land acquisition, the Central Government hereby issues the following guidelines:

i. A copy of the notification, issued by the agency, department or organization responsible for land acquisition for any infrastructure or development project, shall also be shared with the local Forest Department having jurisdiction in the said area.
ii. Joint field verification during land acquisition shall include local Forest Department officials along with revenue officials, wherever felt necessary by the land acquiring Agency, to ascertain the presence of forest land, if any, and prevent subsequent delays due to its identification at a later stage.
iii. In case any type of forest land is identified in joint measurements or joint field surveys, process for its diversion through PARIVESH portal shall be initiated simultaneously by the Project Proponent following due procedure laid down in this regard.

In view of the above, State Governments and UT Administrations are requested to ensure strict compliance with the aforesaid guidelines.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Digitally signed by
CHARAN JEET SINGH
Date: 13-11-2025
19:09:16

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Railways/RT&H/Power/Coal/Mines

2. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
3. Dy Director General of Forests (Central), all Regional Offices of the MoEF&CC
4. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, all States Governments and Union territory Administrations
5. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to upload the Guidelines on PARIVESH.